national companies in the country's economy; and

(b) if so, what are the details thereof

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) The basic framework of our foreign investment policy is laid down in various documents such as Industrial Policy Resolution etc. It is not an open door policy but is selective. It permits technical as well as financial collaboration. Within the broad framework of this policy foreign collaboration/investment will be allowed only in areas considered essential for development of the national economy.

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में पुस्तकालय को चलाने के लिये पर्याप्त धन न होना

338 **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को अपने पुस्तकालय को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उस पुस्तकालय में कानून संबंधी कई पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और अनुसंधान करने वाले छात्रों और वकीलों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नहीं किए गए है,

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार भारतीय विधि संस्थान (इंडियन ला इंस्टीट्यूट) को उसके वार्षिक व्यय को भागत पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान देती है । व्यय के शेष भाग को संस्थान अपने संसाधनों से पूरा करता है । इस सहायता अनुदान की कोई विनिर्दिष्ट रकम पुस्तकालय के लिए सुरक्षित नहीं की जाती है और यह बात संस्थान पर निर्भर करती है कि वह कितनी रकम पुस्तकालय पर व्यय करे । किन्तु, संस्थान के अनुरोध पर, सरकार ने संस्थान को उसके पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें खरीदने के लिए मार्च, 1987 में 2.00 लाख रुपए का अतिरिक्त सहायता, अनुदान मजूर किया था ।

(ख) से (घ) भारतीय विधि संस्थान ने जानकारी दी है कि उन्होंने चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वतनमान का पहले ही पुनरीक्षण कर दिया है ।

सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह संस्थान के संपूर्ण व्यय की सहायता अनुदान के रूप में पूरा करे । किन्तु सरकार ने पहले ही विनिश्चय कर लिया है कि संस्थान के कर्मचारियों के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संस्थान के बढ़े हुए व्यय को भागत पूरा करने के लिए उसका वार्षिक सहायता अनुदान चालू वित्त वर्ष से 6.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया जाए ।

मैसर्स पहारपुर कूलिंग टावर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

339 **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स पहारपुर कूलिंग टावर प्राइवेट लिमिटेड, 13 जज्जेज कोर्ट रोड-कलकत्ता के खिलाफ आयकर चोरी तथा जाली खाते रखने की शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) मैसर्स पहारपुर कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के खिलाफ आयकर चोरी के आरोप की कतिपय शिकायतें आयकर विभाग को मिली थीं । इन शिकायतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्य ह्रास तथा निवेश छूट के गलत दावों और कम्पनी की सहयोगी इकइयों तथा कम्पनी के निदेशकों के पारिवारिक सदस्यों को एक कम ब्याज-दर पर ऋण देने के मामलों का भी उल्लेख किया गया है ।

(ग) उपर्युक्त सूचना के आधार पर दिसम्बर, 1987 में कम्पनी तथा उसके निदेशको की तलाशियां ली गई थीं जिनके परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टया 1.85 करोड़ रुपये के मूल्य की लेखा बाह्य नकदी तथा अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई ।

Meeting of the Committee of Three Chief Justices regarding arrars in Courts

340. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 260 given in the Rajya Sabha on 20th July, 1989 and state:

(a) when the Committee of three Chief Justices met to consider the problem of arrears in courts and also the outcome thereof; and

(b) whether the Law Commission had also given some suggestions in this regard; if so, what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) The Committee has met several times. It has not yet finalised its Report.

(b) Yes, Sir. The Reports of the Low Commission are at various stages of examination.

Subscriptions, contributions and aid given in foreign exchange during seventh five year plan

341. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of subscriptions, contributions and aid given in foreign exchange during the 7th Five Year Plan, indicating the names of the Ministries/State Governments/UT/Administrations which dealt with the matter in each case, the names of foreign countries to which it was given and reasons therefor; and

(b) whether there have been cases where such contributions have been discontinued; if so, detail of cases and the reasons for discontinuance in each case?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Export of Indian Handloom Garments to USA

342. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the export of Indian handloom garments to the United States are expected to go up during the next year as per discussions between officials of the two countries;

(b) If so, what is the expected exports of handloom garments to the United States during the next one Year, as compared to the previous Year; and

(c) whether the unilateral restrictions imposed on the handloom items will affect the export of Indian handlooms and if so what steps are being taken by Government in this regards?